भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2999
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

बीएसएनएल के पुनरुद्धार की रूपरेखा

2999. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए समयबद्ध और परिणाम आधारित पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो वित्तीय लक्ष्यों, उपभोक्ता वृद्धि अनुमानों और सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2014 से बीएसएनएल को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता, साम्या समावेशन, ऋण पुनर्संरचना और स्पेक्ट्रम सहायता का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है और राजस्व, बाजार हिस्सेदारी और नेटवर्क क्षमता के संदर्भ में प्राप्त किए गए मापन योग्य परिणाम क्या हैं;
(ग) 4जी और 5जी सेवाओं के लिए बीएसएनएल को आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम, जिसमें बैंड, मात्रा, मूल्यांकन पद्धति और प्रारम्भ करने की समय-सीमा शामिल है, का ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2014 से अब तक स्थापित किए गए और आगामी तीन वर्षों में लगाए जाने वाले प्रस्तावित मोबाइल टावरों की राज्य-वार और विशेषकर महाराष्ट्र में जिला-वार संख्या कितनी है; और
(ङ) बीएसएनएल को सुदृढ़ करने से विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में वहनीय और सुलभ ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) बीएसएनएल को सुदृढ़ करने और इसे सशक्त, प्रतिस्पर्धी और व्यवहार्य बनाने के लिए, सरकार ने बीएसएनएल को लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये के तीन रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। इन पैकेजों में अन्य उपायों के अलावा पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और 4जी / 5जी स्पेक्ट्रम का प्रावधान शामिल है।

सरकार ने बीएसएनएल को प्रशासनिक रूप से 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए नीलामी में निर्धारित कीमतों पर 700 मेगाहट्र्ज़, 800 मेगाहट्र्ज़, 1800 मेगाहट्र्ज़, 2100 मेगाहट्र्ज़, 2500 मेगाहट्र्ज़ और 3300 मेगाहट्र्ज़ की फ्रीक्यूएँसी बैंडों में स्पेक्ट्रम आवंटित किया है।

बीएसएनएल को दिए गए रिवाइवल पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

(घ) बीएसएनएल ने वर्ष 2014 से 13,748 2जी बीटीएस, 39,722 3जी बीटीएस (नोडबी) और 1,03,305 4जी बीटीएस (ईनोडबी) जोड़े हैं। महाराष्ट्र में बीएसएनएल मोबाइल टावरों का जिलावार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ङ) दूरसंचार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, बीएसएनएल पूरे भारत में संस्थापित के लिए एक लाख देश में बनी 4जी साइटों को रोल आउट कर रहा है। दिनांक 28.02.2026 तक, कुल 97,906 4जी साइटें इंस्टॉल की जा चुकी है और 96,103 4जी साइटें ऑन-एयर हैं।

इसके अलावा, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मांग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों और गांवों तक फाइबर का विस्तार करने के लिए दिनांक 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ के हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रावधान भी शामिल है। बीएसएनएल इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

सीमावर्ती और दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार करने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे 4जी सैचुरेशन योजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) /बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) आदि को लागू कर रही है। इन योजनाओं का विवरण https://usof.gov.in. पर उपलब्ध है।

*****

दिनांक 11.03.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2999 का अनुबंध- I

2014 से महाराष्ट्र में स्थापित बीएसएनएल मोबाइल टावरों का जिलावार विवरण

जिला/एसएसए	इंस्टॉल किए गए टावरों की संख्या
अहमदनगर	220
अकोला	100
अमरावती	147
औरंगाबाद	105
बीड़	90
भंडारा	105
बुलढाणा	75
चंद्रपुर	187
धुले	184
गढ़चिरोली	266
गोवा	96
जलगांव	168
जालना	45
कल्याण	266
कोल्हापुर	157
लातूर	219
नागपुर	274
नांदेड़	97
नासिक	228
उस्मानाबाद	52
परभणी	41
पुणे	252
रायगढ़	159
रत्नागिरी	248
सांगली	58
सतारा	149
सिंधुदुर्ग	220
सोलापुर	90
वर्धा	59
यवतमाल	74

*****